'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.07.2017
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 20 ● अंक 16 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 जुलाई, 2017

परिसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में सम्पन्न

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने 8 जुलाई 2017 को मावलंकर हॉल, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्या नारायण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉ. उदित राज ने 8 जुलाई 2017 को मावलंकर हाल में परिसंघ के देश भर से आए परिसंघ के अध्यक्षों एवं महासचिवों तथा पदाधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्यनारायण की अध्यक्षता में गठित नवनिर्वाचित दिल्ली परिसंघ इकाई को राष्ट्रीय सम्मेलन का शानदार आयोजन के लिए हार्दिक बधाई दी और दिल्ली परिसंघ की टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज को फूल–माला व शॉल भेंट कर स्वागत किया।

परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉ. उदित राज ने परिसंघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि परिसंघ का असली मकसद दलित समाज को मान–सम्मान एवं सशक्त बनाना है और राष्ट्र की बेहतर सेवा के लिए समाज का निर्माण करना है परिसंघ पिछले 2003–2004 से निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है तभी से आज हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है किन्तु परिसंघ को समाज का जो समर्थन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया इसलिए परिसंघ की बहुत सारी मांगे पदोन्नति में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, जाति–प्रमाण पत्र एवं खाली पदों पर भर्ती तथा ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति आदि मांगे पूरी नहीं हो सकी।

डॉ उदित राज ने सम्बोधन में कहा कि बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि राज सत्ता पर कब्जा करो जो कि राजनीतिक दल ही कर सकता है तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? ऐसा नहीं। हमें मिशनरी कार्यकर्ता तैयार करके देश में हर गली मोहल्ले तक परिसंघ की इकाई एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक आंदोलन खड़ा करना है क्योंकि भीड़ की ताकत चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, सरकारें उसी से झुकती हैं। पूर्व में आपने देखा होगा कि जाट आंदोलन और पटेल आंलोदन ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार कितनी भी मजबूत क्यों न हो अपनी मागें मनवाई जा सकती हैं, आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार कितनी ताकतवर है लेकिन जाट आंदोलन की मांगे माननी पड़ी और उन्हें पहले आरक्षण दिया और अब पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने जा रहे हैं।

परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉ. उदित राज निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए पार्लियामेंट में निजी बिल पेश कर चुके हैं जिसको पास कराने के लिए लाखो किरोड़ो का समर्थन चाहिए लेकिन जातिवाद अंबेडकारवादी दुष्प्रचार करके कमजोर कर रहे हैं। डॉ. उदित राज ने परिसंघ की स्थापना वर्ष 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेशों की वापसी के लिए किया था और परिसंघ के संघर्ष के कारण ही तीन संवैधानिक संशोधन हुए और तभी जाकर आरक्षण बचा पाया।

डॉ. उदित राज परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सम्बोधन में बताया कि गत 15 वर्षो से मुख्य हमला उनके ऊपर जातिवादी व अंबेडकरवादी ही करते आ रहे हैं डॉ. राज ने कहा कि कोई उनकी एक गलती तो बता दे। जब भाजपा में शामिल नहीं थे तब भी उन पर अलग–अलग आरोप लगते रहे। क्योंकि जो समाज के हित के लिए काम करता है आगे बढ़ता है उस पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं यह समाज का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को दलित समाज समझ नहीं पा रहा है। डॉ. उदित राज आज दलित समाज के उत्थान के लिए जितने चिंतित हैं, शायद ही कोई ओर नेता हो। जिस कांग्रेस ने पृथक मताधिकार जो बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर चाहते थे वह होने नहीं दिया फिर भी

डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा को फूल–माला अर्पण करते हुए डॉ. उदित राज जी व साथ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्या नारायण, महासचिव भानू पुनिया व अन्य पदाधिकारी

डॉ. उदित राज जी का स्वागत करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्या नारायण व अन्य पदाधिकारी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

(पृष्ठ शेष 1 का)

बाबा साहेब उसी कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आ गए, मंत्री बने और संविधान बनाने का मौका मिला। समाज व परिसंघ की सहमति पर डॉ. उदित राज भाजपा से चुनकर के संसद में गए और दलित समाज की समस्याओं को उठाया, अगर आवाज नहीं उठाते तो बाबा साहब के पदचिन्हों पर न चलना कहा जा सकता था। डॉ. उदित राज ने पिछले तीन साल में अब तक कितने सवाल पार्लियामेंट में उठाये शायद ही किसी सांसद ने उठाये होगे। अगर आज परिसंघ के कार्यो का मूल्यांकन करें तो किसी मुख्यमंत्री, छोटे-मोटे दल से कई गुना ज्यादा है, आलोचक अब भी सावधान हो जाएं और अंबेडकरवादी प्रमाण के रूप में परिसंघ का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की जानकारी ले लें, कि क्या उन्होंने अपनी जाति उपजाति वालों को संगठन में स्थान दिया है? एक अंबेडकरवादी उपयोगिता और भागीदारी के आधार पर संगठन में जगह देता है न कि जाति के आधार पर किसी भी संगठन और नेताओं में खुली बहस के लिए तैयार है, अगर हम सही हैं तो साथ आ जाओ और अगर तुम सही हो तो हम आपके साथ आ जाएंगे। हर हाल में एक होना पड़ेगा वरना निजीकरण? भूमंडलीकरण के दौर में आरक्षण तो खत्म हो ही रहा है दूसरी तरफ मानसिक गुलामी बढ़ रही है ।

डॉ. उदित राज राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए अलग-अलग राज्यों के जन समूह के साथ

डॉ. उदित राज जी ने दिल्ली देहात की मुख्य मांग 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत मिली हुई जमीन की भूमि धारी के अधिकार की आवाज पिछले 2-3 वर्षो से केंद्र सरकार से लगातार उठा रहे हैं। मालिकना हक देने के लिए डॉ उदित राज ने देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी, गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री श्री वेंकइयानायडू, ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजीरीवाल से मुलाकात की और जल्द ही दलितों को उनका हक मिलने वाला है।

डॉ उदित राज जी ने श्रीमती सविता कादियान पवार को हाल ही में परिसंघ की महिला प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक व अर्चना भोयर को सह-संयोजक नियुक्त किया है। सविता जी, अर्चना जी तभी से दिल्ली और देश के कोने-कोने में जाकर महिला प्रकोष्ठ को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। यह महिला विंग का एक सराहनीय कदम है। महिला भागीदारी पर डॉ उदित राज जी ने खुशी जाहिर कर आगे बढ़ने का साहसिक कदम बताया ।

परिसंघ दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सत्या नारायण ने कहा कि परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉ. उदित राज ने जितना विश्वास हमारे ऊपर किया दिल्ली परिसंघ देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा शतक और मजबूत करने का प्रयास करेगा। दिल्ली परिसंघ के तत्वाधान मे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने में परिसंघ के महासचिव श्री भानु पूनिया, श्री हरि प्रकाश, देवी सिंह राणा, दया राम, रवींद्र कटारिया, आर एस हंस, जगदीश मालिक, संजय सिंह, करम सिंह, डॉ सागर, दया नन्द, मुकेश कुमार, आर. सी. मथुरिया व आर. के. वर्मा, गणेश येरेकर व दिल्ली देहात के महासचिव श्री अशोक अहलावत व उपाध्यक्ष श्री सतबीर पचेरवाल ने दिन-रात मेहनत करके कार्यक्रम को सफल बनाया ।

सत्या नारायण
अध्यक्ष दिल्ली परिसंघ
9873988894

***

राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का परिचय करते हुए

परिसंघ दिल्ली के विभिन्न लोक सभा क्षेत्रों में कार्यकर्त्ता सम्मेलन सम्पन्न

परिसंघ के लोक सभा क्षेत्रों के कार्यकर्त्ता सम्मेलन संगठन को मजबूत करने हेतु आयोजित किए गए। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्र का सम्मेलन पहले ही किया जा चुका था। 14 जून को करोल बाग एवं नई दिल्ली, 16 जून को दक्षिण दिल्ली एवं 18 जून को पूर्वी दिल्ली लोक सभा क्षेत्र का सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री परमेन्द्र, राष्ट्रीय सचिव, परिसंघ ने कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को जो बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया गया था, आज वह एक-एक करके खत्म होते दिख रहा है, जो कि गलत है। अब हम लोग चुप नहीं रहेगें। आरक्षण बचाने के लिए पूरे देश में परिसंघ के बैनर तले लोगों को कैडराइज कर के संगठन को मजबूत करते हुए देशव्यापी आंदोलन करेगें और अब हम निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग लगातार कई सालों से कर रहे हैं, साथ ही साथ पदोन्नति में आरक्षण पुनः बहाल किया जाए। यह लड़ाई परिसंघ के नेतृत्व में डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में चल रहा है। अंत में संगठन का विस्तार किया करते हुए विधान सभा स्तर के निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किए गए :-

विधान सभा	पद	पदाधिकारी का नाम
करावल नगर	प्रभारी	विजय कुमार
करावल नगर	अध्यक्ष	डॉ. देवेन्द्र कुमार
करावल नगर	उपाध्यक्ष	सी.पी. सिंह सूर्यवंशी
करावल नगर	महामंत्री	प्रमोद कुमार
मुस्तफाबाद	प्रभारी	संतोष कुमार राठौर
मुस्तफाबाद	अध्यक्ष	मनीष सूर्यवंशी
घोंडा	प्रभारी	मुकेश तोमर
रोहतास नगर	प्रभारी	मदन लाल
अम्बेडकर नगर	प्रभारी	भगवान दास पहाड़िया
संगम विहार	अध्यक्ष	सुशील खटीक
संगम विहार	उपाध्यक्ष	मुन्नी लाल
संगम विहार	महामंत्री	विनोद कुमार
देवली	अध्यक्ष	भूपेन्द्र कुमार
देवली	उपाध्यक्ष	गंभीर सिंह राजौरा
देवली	महामंत्री	अमर सिंह
तुगलकाबाद	प्रभारी	राजू भारती
तुगलकाबाद	महामंत्री	जयसिंह मनोहर
तुगलकाबाद	मंत्री	बब्लू
छत्तरपुर	प्रभारी	सुशील कुमार कसौदिया
छत्तरपुर	उपाध्यक्ष	रोहित कुमार
छत्तरपुर	मंत्री	विजय कुमार
ओखला	प्रभारी	सविता
ओखला	अध्यक्ष	डॉ. भरत सिंह
पटेल नगर	प्रभारी	देवेन्द्र कुमार
पटेल नगर	अध्यक्ष	विनोद कुमार पिहाल
पटेल नगर	सचिव	रमेश
सदर	प्रभारी	मंगल विश्वास
सदर	अध्यक्ष	सुदामा
सदर	महमंत्री	विष्णु
सदर	कोषाध्यक्ष	रामजीत
लोनी	प्रभारी	महेन्द्र खटीक
लोनी	अध्यक्ष	मोनू मुंडे

- बाबू लाल संगठन मंत्री, दिल्ली
मो. 9918023024

***

परिसंघ के सदस्य बनें और सोसल मीडिया से जुड़े

डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में चल रहे ऑल इंडिया परिसंघ की स्थापना 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी के लिए हुआ और तब से लगातार संघर्ष करते हुए अनेको अधिकार सुरक्षित कराए। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। आप परिसंघ के सदस्य बनकर इस आंदोलन को सहयोग कर सकते हैं। आप उपलब्धियों और गतिविधियों की लगातार जानकारी के लिए परिसंघ के सोसल मीडिया एकाउंट **www.facebook.com/aiparisangh** को लाइक करें। **twitter.com/aiparisangh** पर फालो करें। **Whatsapp No. : 9899766443** को अपने फोन में सेव करें और किसी भी जानकारी के लिए **parisangh1997@gmail.com** पर ईमेल करें। अधिक जानकारी हेतु सुमित मो. नं. **9868978306** पर सम्पर्क करें।

- सत्यानारायण, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, परिसंघ, मो . 9873988894

जी.एस.टी. से डर क्यों ?

– डॉ. उदित राज

1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर लागू हो गया है। कुछ जगहों पर पहले से ही हाय तोबा मच गयी थी। प्रश्न यह पैदा होता है कि जब खुद कठिनाई का अनुभव न हो तो उसके पहले इतना भय क्यों? भारतीय समाज को परिवर्तन के प्रतिकूल रहने की एक प्रवृत्ति है, सिवाय जहां कि खुद का स्वार्थ न हो। जब मोबाइल कंपनियां आने लगी थी तो ऐसे भी विज्ञापन आते थे कि एक दिन हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होगा, चाहे वह मजदूर हो या किसान? लोग इसे मजाक समझते थे कि अनपढ़ लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगें? आशय यह था कि कंपनियां बढ़-चढ़कर विज्ञापन दे रही हैं और अंग्रेजी में मोबाइल में लिखे अंक को पढ़कर फोन करना क्या आसान हो जाएगा? चूंकि यह आवश्यकता थी इसलिए क्या पढे-लिखे क्या अनपढ़ सभी इस्तेमाल करने लगे। कभी-कभी तो अनपढ़ जितना मोबाइल के बारे में जानकारी रखते हैं, उतना पढ़े-लिखे नहीं, क्योंकि यह उनकी रुचि और स्वार्थ की वस्तु हो गयी है। समय इनके पास होता है तो इस पर गाना, फिल्म और समाचार आदि भी सुनते और देखते हैं। अगर जी.एस.टी. को स्वयं के उपयोग की भांति न केवल देखकर भविष्य और देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगें तो कुछ भी मुश्किल नहीं।

इस बात का बड़ा जोर-शोर है कि जी.एस.टी. से परेशानी बढ़ेगी। शुरुआत में किसी भी अच्छे काम में मुश्किलें तो आती ही हैं। मोबाइल फोन का उदाहरण समझने के लिए उपयुक्त है। शुरु में काल दर बहुत महंगी थी, बात करते-करते कट भी जाता था, फिर भी लोगों की जिज्ञासा रहती थी कि सबके पास मोबाइल हो। पूर्व की कर-प्रणाली को सही रूप से यदि हम लागू किए होते तो जी.एस.टी. से कहीं ज्यादा जटिल थी। चूंकि उस प्रणाली में बचने की गुंजाइस ज्यादा थी, इसलिए वर्तमान व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। अभी जो 37 फार्म भरने की जटिलता बताई जा रही है, वास्तव में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति एक बार बेचेगा वही फार्म भरना पड़ेगा, खरीददार को उसी को डाउनलोड करना है और फिर दोनो का संग्रह। इस तरह से प्रत्येक स्तर पर सिवाय शुरुआत की बीच की कड़ी के अलावा बाद वालों को डाउनलोड ही करना है। हमारे देश में जब समाज और देश के भले में कोई काम करने

की बात आती है तो उसमें सारी जटिलताएं जैसे इंस्पेक्टर राज, कागजी कार्यवाही का बढ़ना इत्यादि लेकिन जब वही काम स्वयं के लाभ के लिए करना हो तो पड़ोसी को भी हवा नहीं लगने देते।

निजीकरण, भूमण्डलीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था के कुछ नुकसान हैं, जैसे कि रोजगार का कम होना और पूंजी का संग्रह कुछेक के हाथों में। लाभ कमाने के लिए तकनीक का ज्यादा उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने की होड़ लगी रहती है और इसका प्रतिकूल असर यह होता है कि कम से कम कर्मचारी और मजदूर लगाए जाएं। जी.एस.टी. से कुल सकल घरेलू उत्पाद में इजाफा होगा और इससे रोजगार की बढ़ोत्तरी होना तय है। न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि इससे प्रत्यक्ष कर में भी काफी इजाफा होगा। जब दुनिया में लगभग 160 देश जी.एस.टी. को लागू कर चुके हैं तो भारत कितने दिनों तक इसे रोक सकता था। इससे पूरा देश एक बाजार हो जाएगा और वस्तुएं सस्ती होगीं। जब वस्तुएं सस्ती होगीं तो आम आदमी का फायदा होना तय है। प्रत्येक राज्य की सीमा पर हजारों ट्रकों का जो जाम होता था, उससे मुक्ति मिलेगी और इससे न केवल व्यापारियों को लाभ मिलेगा बल्कि जो भी आवागमन कर रहा है।

डिजिटाइजेशन जितना ही बढ़ेगा उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। इसका असर केवल वस्तु और सेवा के क्षेत्र में ही नहीं होगा, बल्कि सब जगह पर होगा। इसकी वजह से कुछ लोगों को न इरादा होते हुए भी डिजिटाइजेशन की ओर जाना होगा लेकिन देश हित में कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है। आखिर में यह डर क्यों है? उसका मुख्य कारण है कि जो लोग लगभग 30 प्रतिशत कर न अदा करके कच्चे में काम करते थे अब उन्हें पक्के में करना ही पड़ेगा। उन्हें भी समझना चाहिए कि जितना ज्यादा पक्के में खरीद और बेंच खातावही में दिखाया जाएगा, उतना व्यापार में इजाफा होगा। बहुत लोग व्यापार करने के लिए पूंजी इसलिए नहीं दिखा पाते हैं कि उनके पास कालाधन तो है, लेकिन सफेद नहीं और इसलिए कभी हवाला का सहारा, कभी दान का, कभी कृषि आय आदि-आदि। दुनिया में जो देश एक ही जीवन में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, उन्होंने कच्चे में नहीं बल्कि पक्के में काम किया। दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय हमसे 26 गुना ज्यादा है। उन्होंने भी तो एक ही जीवन में इस तरक्की को करके दिखा दिया।

मोदी सरकार की इच्छाशक्ति है कि अंततः जी.एस.टी. लागू कर ही दिया। सरकार की कोई नीति लागू करने से पहले ही क्यों कुछ लोग मान बैठे हैं कि इससे व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कुछ के लिए यह भी संशय है कि इससे खुदरा व्यापारी खत्म हो जाएंगें । जो काम दुनिया के तमाम देशों में हो चुका है और वह सफल है तो उसको करने में डर क्या? जो दो मूल बातें हैं जिसकी वजह से हायतोबा का माहौल है, वह यह है कि अब कच्चे में काम करना मुश्किल हो जाएगा और दूसरा कि हम भारतीय परिवर्तन को जल्दी से अपनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते।

***

कश्मीरी पंडितों की 'जन्मजात श्रेष्ठता' पैरों तले रौंद

डीयू की मेरिट में आगे निकले 'आरक्षण वाले' छात्र

नई दिल्ली। नेशनल जनमत ब्यूरो।

जब भी आरक्षण की बात होती है, मेरिटवादी लोग किसी आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट की मानसिक प्रताड़ना का आंकलन किए बगैर अवसरों की समानता के इस संवैधानिक तरीके को गाली देना शुरू कर देते हैं। वो शायद ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मणों के जन्मजात श्रेष्ठ होने और मुख से पैदा होने की थ्योरी उन्हीं जैसे जातिवादी लंपटों की देन है।

अब समय बदला है 70 साल के अवसरों में ही आरक्षित वर्ग ने पटखनी देना शुरू कर दिया है। आरक्षित वर्ग को पढ़ाई-लिखाई से वंचित रखके उनसे समानता के अवसर छीनने वालों की जन्मजात श्रेष्ठता थ्योरी लगातार ओबीसी-एससी-एसटी छात्रों द्वारा पैरों तले रौंदी जा रही है। हालिया उदाहारण दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध हिन्दू कॉलेज की पहली कट ऑफ का है। जहां ग्रेजुएशन के 18 विषयों की कट ऑफ में से ज्यादातर में आरक्षित वर्ग के छात्रों ने कश्मीरी पंडितों के दंभ को चकनाचूर कर दिया है।

18 में से 14 विषयों में कश्मीरी पंडित ओबीसी से पीछे-

हिन्दू कॉलेज की कट ऑफ के अनुसार 18 में से 14 विषय ऐसे हैं जिनमें या तो ओबीसी के छात्र-छात्राएं कश्मीरी पंडितों के बराबर अंक पर सिलेक्ट हुए हैं या उससे कहीं ज्यादा पर। फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथमैटिक्स, जूलॉजी जैसे विषयों में ओबीसी छात्रों की कट ऑफ कश्मीरी पंडितों से बहुत आगे है।

6 विषयों में एससी छात्रों ने पटखनी दे दी विशुद्ध आर्यो को-

यह पोस्ट विशेष रूप से 'मेरिटधारियों' के लिए है।

देश का प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय, में आज से स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय और देश का एक नामचीन कॉलेज है ''हिन्दू कॉलेज। आज हिन्दू कॉलेज की पहली कट ऑफ आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है, विभिन्न कोर्स में SC/ST/OBC और General श्रेणी के कट ऑफ का विश्लेषण तो आप कर ही लेंगे। मैं उदाहरण के लिए दो समूह के कट ऑफ मार्क्स को आपके सामने रख रहा हूँ। SC और Kashmiri Migrants (अर्थात् विशुद्ध 'आर्य', बाकी आप समझ लें)

BA (H) History – SC (95-75%)

***

लेने से पहले कुछ देना सीखो : डॉ. उदित राज

मनीष सुर्यवंशी

उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार में वीरसूर्या टाइम्स के तत्वाधान में बाबा साहब अंबेडकर की 126वीं जयंती समारोह एवं दलित उत्थान परिचर्चा का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद डॉ. उदित

राज जी सम्मिलित हुए। माननीय सांसद के साथ लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर लोगों को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज ने कहा कि यदि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर न होते तो दलितों में से कभी सांसद, विधायक, पार्षद व प्रधान तक नहीं बन पाते लेकिन बाबा साहब की आरक्षण की बदौलत ही दलित अधिकारी नेता बन पाते हैं किंतु दुख की बात है कि लोग बाबा साहब की कुर्बानी को भूल जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धीरे-धीरे सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है। अपने बच्चों को कितना पढ़ा-लिखा लो लेकिन नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। अगर दलित जाति के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब आरक्षण भी खत्म होने के

(शेष पृष्ठ 6 पर)

परिसंघ के महिला प्रकोष्ठ का प्रथम सम्मेलन संपन्न

15 जून 2017 को टैक्निया आडिटोरियम, मधुबन चौक नियर रोहिणी कोर्ट, रोहिणी मे परिसंघ की राष्ट्रीय महिला संयोजक 'सविता कदियान पंवार' के नेत्तृत्व मे कार्यक्रम 'महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर संगोष्ठी' सफलतापूर्वक आयोजित की गई । जिसमें पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद व परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज जी रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन 'उत्तर पश्चिम जिले की महिला टीम की अध्यक्षा श्रीमती 'सुनीता केम' जी ने सफलता पूर्वक संभाला। कार्यक्रम की शुरूआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर हुई। साथ ही महिला मंडल टीम द्वारा बुद्ध वंदना द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई ।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज जी ने कहा कि जब तक इस देश में महिलाओं को आज़ादी नहीं दी जाती। उनका उत्पादन में बराबर का सहयेाग नहीं होता, शिक्षा में व बाहर के कामों में भागीदारी नहीं होती तब तक कोई यह कहे कि देश चीन या कोरिया का मुकाबला कर लेगा संभव नहीं है। लगभग तीन हजार वर्षो के इतिहास में महिलाओं का घर के मामले में फैसले का अधिकार नहीं है। ऐसा दूसरे समाज में नहीं है। कभी दूसरे समाजों में भी ऐसा होता था लेकिन जो देश तरक्की कर गए हैं, वहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बाहर काम करती हैं, चाहे होटल चलाने का काम हो, टैक्सी चलाने का काम हो या मिल चलाने का हो, ये सभी कार्य महिलाएं पुरूषों से ज्यादा करती हैं। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ यूक्रेन में गया तो उस मार्केट में ज्यादा औरतें ही दिखाई दीं तो मेरी पत्नी ने कहा कि यहां के मर्द कहां हैं। हमने कहा कि यह देश और यह समाज समानता वाला है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी यहां ज्यादा है। कंबोडिया, थाईलैंड, यूक्रेन, जापान आदि में रात को एक या दो बजे तक लड़कियां और औरतें दुकान बंद करके घर जाती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक महिलाओं को भागीदारी सभी क्षेत्रों में नहीं मिलती तब तक हमारा देश विकसित देशों की कगार में खड़ा हो जाए यह सपना ही रह जाएगा। यहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षिकाएं भी बैठी हैं अन्य विभागों की महिलाएं भी यहां बैठी हैं, लेकिन इस प्रकार की महिलाओं की संख्या आधा प्रतिशत भी नहीं होगी, तो ऐसे में इसे महिलाओं का उत्थान नहीं कहा जा सकता। सबसे ज्यादा महिलाओं को आजादी और स्वतंत्रता की बात अगर किसी ने की तो वे सामाजिक न्याय के योद्धाओं जैसे पेरियार और डॉ0 अम्बेडकर ने की। डॉ. अम्बेडकर की किताबों और लेखन में हमेशा महिलाओं के उत्थान की ही बात की गयी है। ज्योतिबाफुले जिसे डॉ. अम्बेडकर ने अपना गुरू माना, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें पढ़ाया और स्कूल खोलकर उन्हें शिक्षिका के रूप में स्थापित किया। उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ाने की बात तो दूर। उन्हें दो साड़ी लेकर जाना पड़ता था। रास्ते में उन पर गोबर फेंका जाता था, स्कूल पहुंचकर वे साड़ी बदलती थी तो पढ़ाती थी। ज्योतिबाफुले ने अपने घर में सबसे पहले इसे लागू किया । हम लोग अपने घर में नहीं करते बल्कि पड़ोसी से उम्मीद करते हैं। पेरियार जी ने कहा कि महिलाओं पर सबसे बड़ा बोझ उनका चरित्र है। वे अपना चरित्र और लोक लज्जा लेकर घूमती रहती हैं कि कोई लांक्षन न लगा दे। पुरुष कुछ भी करे हमेंशा उसकी मूंछ ऊपर रहती है। कुछ गलत भी करता है तो लोग कहते हैं बड़ा स्मार्ट आदमी है। यदि वही काम महिला करे तो उसका चरित्र हनन हो जाता है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद दोनों बातों को रखना है कि महिला किसी भी समाज में पैदा हुई है तो उसकी समस्या यही है। दलित समाज में पैदा होने पर दोहरी मार पड़ती है, पहली दलित होने के कारण छुआछूत की शिकार, तो दूसरी महिला होने का। बड़े दुख की बात है कि पूरे देश में मैंने देखा महाराष्ट्र को छोड़कर कि दलित, आदिवासी व पिछड़े समाज की महिलाओं का नेतृत्व उभरकर नहीं आता। किसी और के नेतृत्व में हो सकता है कि धरना-प्रदर्शन व अपने अधिकारों की मांग करें लेकिन इनका नेतृत्व मैंने नहीं देखा। इनका नेतृत्व उभरना चाहिए, इसी सोच के साथ सविता जी ने जिम्मेदारी ली है। नागपुर से अर्चना भोयर जी हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली है और धीरे-धीरे कारवां बढ़ रहा है। ये लोग कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद आदि सुदूर क्षेत्रों में जाकर नेतृत्व कर रही है। यहां पर कई कॉलेजों, जैसे अम्बेडकर कॉलेज, जाकिर हुसेन कॉलेज आदि की छात्राएं आयी हुई हैं। कल मैं एक छात्रा से बात कर रहा था तो उसने कहा कि मैंने आरक्षण का फायदा नहीं लिया है, मैने कहा कि आरक्षण का फायदा लेकर ही यहां तक पहुंचे हो, प्रत्यक्ष रूप से ले लो या अप्रत्यक्ष रूप से ले लो। क्या 70-80 वर्ष पहले आपके पुरखे कलेक्टर, जज, एम.पी., एम.एल.ए., या प्रधान चुने गए थे या अधिकारी बने थे? उससे पहले दलित गांव के बाहर बसाए गए थे, वे अस्पृश्यता के शिकार थे, अपनी मर्जी का व्यवसाय नहीं कर सकते थे। मान लिया जाए कि जो दलित छात्र-छात्राएं आज आरक्षण का फायदा नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी आरक्षण की वजह से ही फायदा हुआ है, क्योंकि आरक्षण के कारण ही देश में माहौल बदला और इन्हें पढ़ने-लिखने या कुछ भी विकास करने का अवसर मिला। 1970 या 1960 में कोई दलित लड़की आई.ए.एस. या आई.पी.एस. टॉपर नहीं बन सकती थी जबकि आज बन पा रही हैं। इस मुकाम तक पहुंचने में 3-4 पीढ़ियां लग जाती हैं। जो आज टॉप कर रहे हैं, उनके माता-पिता आरक्षण का लाभ लेकर आगे आएं हैं। जिनकी सैकड़ों पीढ़ियां शिक्षित रही हैं, वे तो पहले से ही जागरूक हैं, इसलिए उन्हें तो लाभ मिलता ही है। बहुत सी चीजें पारिवारिक संस्कार से आती हैं, जैसे बात-चीत करने का तरीका, रहन-सहन, चतुराई आदि। हमारे समाज को किसी से फायदा लेना कम आता है। जिनकी पीढ़ियां चतुर रही हैं वे गर्दन भी मुस्कराकर काट लेते हैं। हाल ही में दो लोग मेरे कार्यालय में आए, उनमें से एक न्यूमोरोलोजिस्ट थे, जो कहते हैं कि भविष्य बताते हैं, तो मैंने कहा कि सच बोल दूं, तो कहा हां बोलो। तो मैंने पूछा कि देश पर किस तरफ से हमला होने वाला है? क्या नोटबंदी के बारे में आपको पहले से पता था? अच्छा यह बता दो कि आपके साथ कल क्या होने वाला है? मैंने कहा कि भविष्य बताने के चक्कर में ही देश दो हजार सालों तक गुलाम रहा। क्या एक भविष्य वाणी ये नहीं कर पाएं कि मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने वाला है? सिकन्दर आक्रमण करने वाला है। जलियावाला कांड में सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया, मरने वालों को आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बताया गया। उस घटना के बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जनरल डायर जो इस घटना का दोषी था, को क्यों सम्मानित किया गया था? मैंने पूछा कि उनका स्वागत क्यों हुआ तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं है। वास्तव में हुआ यह था कि यहां से लोगों को विदेश में भी सिपाही बनाकर भेजा गया। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध अंग्रेजों ने भारतवासियों को भाड़े पर लेकर लड़ा। मैं दर्बन गया था, वहां पर 15 लाख भारतीय हैं, मैंने पूछा कि यहां आए क्यों थे तो पता लगा कि दर्बन में गन्ने की खेती अच्छी होती है, वहां पर गन्ने की खेती में काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते थे, इसीलिए भारतीयों को लाया गया था। हमारे लोग जातियों को पहले प्यार करते हैं, देश के प्रति प्यार बाद में आता है। यही कारण था कि जो विदेशी आए, हमारे ही लोगों को भाड़े पर लेकर हमारे देश पर ही राज किया। अंग्रेज जब हमारे लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए ले गए तो वे विदेशी लोगों के साथ एक-डेढ़ साल तक रहे और पता लगा कि वहां भेदभाव नहीं है। तो उनके अंदर बदलाव आ गया और जब वापिस यहां लाए गए तो उन्होंने कहा कि हम भी स्वर्ण मंदिर के दर्शन करेगें। तब मंदिर के प्रबंधकों ने कहा कि ये दलित कैसे दर्शन कर सकते हैं? जब स्वर्ण मंदिर में इजाजत नहीं मिल रही थी तो उसके बाद भी वे स्वर्ण मंदिर में घुसने के लिए आमादा थे। इसके बाद प्रबंधकों ने जनरल डायर से कहा कि इनको रोका जाए तो अंग्रेजों की पुलिस ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वे रुके नहीं तो गोली चलानी पड़ी तो कई सौ लोग मारे गए। तो इतिहास में कहा गया कि वे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए मारे गए। दरअसल वे सामाजिक बंधन की लड़ाई लड़ रहे थे। इतिहास में सही बात लिखी ही नहीं गयी। कहने का मतलब है कि इस देश को जाति व्यवस्था ने गुलाम बनाया, इसकी वजह से हमारे उत्पादन पर असर पड़ा, भौगोलिक व्यवस्था पर इसका असर पड़ा, हमारी सोच, स्वास्थ्य आदि पर असर पड़ा। ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल क्यों नहीं ले पाते? सवा सौ करोड़ लोगों से चुने गई टीम के लोग पाकिस्तान से क्रिकेट खेलें, बराबरी पर छूट जाएं या फिर जीत भी जाएं तो क्या यह हमारे लिए सम्मान की बात है? हमारी क्वालिटी तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी टीम सबसे बड़ी आबादी वाले देश से चुनकर जा रही है। लेकिन होता यह है कि हम छोटे-छोटे देशों से जूझते रहते हैं। न्यूजीलैंड जैसे देश, जिसकी आबादी मेरे लोक सभा क्षेत्र के बराबर है, उससे हम जूझते हुए मिलते हैं। कभी हम इनसे जीत जाते हैं तो क्या यह हमारे लिए गर्व की बात है। यहां मेरा कहने का आशय यह है कि सामाजिक व्यवस्था से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ा अफ्रीका जैसे देश में देखते हैं कि वहां के पुरुष ही नही बल्कि महिलाएं भी कितनी शक्तिशाली होती हैं। इसलिए साबित होता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण ही हम गुलाम बने, कमजोर बने, फिर भी हमारे देश के लोग इस पर विचार करने को तैयार नहीं हैं। कहने को तो हम अगले 200 सालों तक कहते रहेगें कि हम आगे बढ़ रहे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं। कोई भी देश ग्लोबल पॉवर बन नहीं सकता जब तक उसके सभी नागरिक शिक्षित न हों। हमारे यहां आधा-एक प्रतिशत लोगों को ही गुणवत्ता वाली शिक्षा निजी स्कूलों में मिल पा रही है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में भेजना नहीं चाहता। नगर निगम व राज्य सरकारों

डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए डॉ. उदित राज व महिला प्रकोष्ठ की टीम

मंच पर डॉ. उदित राज के साथ सविता कादियान पवार

(शेष पृष्ठ 6 पर)

यू.पी.एस.ई. का भेदभाव

31 मई, 2017 को संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम नतीजा आया, जिसमें 1090 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। यह सभी जानते हैं कि तीन स्तर पर इसकी परीक्षा होती है। पहली प्रारंभिक, दूसरी मुख्य और तीसरी साक्षात्कार। प्रथम और द्वितीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली की वजह से जाति नहीं पता लग पाती लेकिन सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के लिए अलग-अलग साक्षात्कार बोर्ड बनते हैं। इस तरह की व्यवस्था इसलिए होती है कि जो दलित और पिछड़े हैं वे सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों की प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में पीछे हैं, इसलिए इनका मूल्यांकन अलग से हो ताकि न्याय मिल सके। संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार के अंकों को जब जांचा गया तो यह स्पष्ट हुआ कि अलग से साक्षात्कार की व्यवस्था हानिकारक ज्यादा है और लाभकारी कम।

अनुसूचित जाति के 163, जन जाति के 89, पिछड़े वर्ग के 347 और सामान्य वर्ग के 500 परीक्षार्थी विभिन्न सेवाओं के लिए चुने गए। साक्षात्कार में अनुसूचित जाति को औसतन 163, जन जाति को 166, पिछड़े वर्ग को 164 एवं सामान्य वर्ग को 170 अंक दिए गए। साक्षात्कार की व्यवस्था अलग-अलग इसलिए की गयी ताकि विभिन्न वर्ग के परीक्षार्थी अपने में ही प्रतिस्पर्धा करें। अगर ऐसा नहीं होना था तो अलग से साक्षात्कार की व्यवस्था करना ही नहीं चाहिए था। हो सकता है जाति न जानने की परिस्थिति में इनको अच्छे अंक मिल सकते थे और ऐसा कई विभागों में देखा गया है। ये भेदभाव करने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो नहीं थे बल्कि अपने ही समाज के थे।

सामन्य वर्ग के लोगों में ईर्ष्या होती है कि कम योग्यता वाले आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और अन्य सेवाओं में कम अंक प्राप्त करके चले जाते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसी परीक्षा व्यवस्था नहीं बनी है जो किसी भी व्यक्ति की पूर्ण क्षमता, गुण और ज्ञान किसी एक रिपोर्ट-कार्ड में समाहित कर दे। एक-दो सवाल ज्यादा हल करने से कुछ अंक बढ़ जाते हैं और ऐसे लोग सामान्य श्रेणी में पास करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि थोड़ा कम अंक प्राप्त करने वाले अयोग्य हैं। जो भी इन सेवाओं के लिए चुने जाते हैं, उनकी असली परीक्षा प्रशिक्षण के बाद जब व्यवहार में जिम्मेदारी मिलती है, तब पता लगता है कि किताबी ज्ञान में जो आगे थे और व्यवहार में जरूरी नहीं है कि आगे ही रहें, और यह अक्सर देखा भी गया है। जहां तक परीक्षा में अंक प्राप्त करने की बात है, या व्यक्तित्व का विकास या बात-चीत करने का तरीका, ये ज्यादातर घर और

जाति से ही मिलते हैं। जो लोग 50 और 100 पीढ़ियों से पढ़ते आए हैं उनके बच्चे स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व, शिक्षा और रहन-सहन में बेहतर होगें। जिनको पीढ़ियों का फायदा नहीं मिला है, उनको अवसर मिलता है तो कुछ समय में बराबरी कर लेते हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से बेहतर उदाहरण समझने के लिए शायद कोई और न होगा। वहां पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के परिवेश से आने वाले छात्रों को कुछ अंकों की वरीयता दी जाती है, जिससे वे प्रवेश पा जाते हैं। वहां पर सेमिस्टर सिस्टम है, प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में ऐसी पृष्ठिभूमि के छात्र पीछे रहते हैं और तीसरे में लगभग बराबरी पर आ जाते हैं और अंत में कई ऐसे हैं, जो सबसे आगे निकल जाते हैं। कुल मिलाकर सवाल है, अवसर प्राप्ति का। नेपोलियन ने कहा था कि अवसर के बिना योग्यता का कोई मतलब नहीं। पिछले वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में टॉप करने वाली दलित समाज की थीं। इस वर्ष की जेईई में भी दलित छात्र ने 100 प्रतिशत अंक लेकर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है हालांकि ये अपवाद ही हैं। यह अपवाद 1960-70 और 80 के दशक तक संभव नहीं था। पीछे की पीढ़ियों का ज्ञान और रहन-सहन का फायदा इन्हें मिला और उसके अलावा माहौल का भी। पहले लगभग सभी परीक्षाओं में पास होने वाले अंको में बड़ा अंतर होता था लेकिन धीरे-धीरे अब कम होता जा रहा है और आगे आने वाली दो-चार पीढ़ियों में यह अंतर खत्म हो जाएगा।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बनी, जहां विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू हो गयी थी। उसी पृष्ठभूमि से अंग्रेज भारत में आए और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में वही पास होते थे और भारतीय नहीं के बराबर तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय जन्म से उनसे कम योग्य थे? जब भारतीय परीक्षा पास नहीं कर पा रहे थे तो दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ कि भारतीयों को नौकरशाही में भागीदारी दी जाए। जब भारतीय अंग्रेजों के मुकाबले में परीक्षा में कम अंक प्राप्त करते थे और पास नहीं हो पाते थे तब तृतीय श्रेणी की प्रणाली शुरू की गयी, इससे पहले प्रथम एवं द्वितीय ही होती थी। अब अगर यूरोप और अमेरिकी लोगों से तुलना की जाए तो भारतीयों और उनके बीच अंतर बहुत कम हुआ है। यहूदियों में हजारों वर्षों से शिक्षा प्राप्त करने की परंपरा रही है इसलिए आज भी औरों से आगे हैं। इसीलिए मुट्ठी भर आबादी वाला देश इजराइल में सैकड़ों नोबेल पुरस्कार वाले मिल जाएगें। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सैकड़ों नोबेल पुरस्कार वाले हैं।

सबकी भागीदारी और समानता से देश मजबूत होगा। जो लोग सोचते हैं कि इससे योग्यता पर असर पड़ेगा वे बार-बार सोंचें कि इनका यह विचार गलत है। जब दलितों और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो इनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी तो सामान किसका बिकेगा? ज़ाहिर है कि दलित आदिवासी उद्योग और बाजार में हैं नहीं, तो लाभ तथागत सवर्णों का ही होगा। जिन लोगों ने साक्षात्कार में नंबर कम दिया उन्होंने देश को कमजोर करने का ही काम किया है। अपील है कि सबकी भागीदारी होने दें और देश को आगे जानें दें।

– डॉ. उदित राज, सांसद
राष्ट्रीय चेयरमैन,
अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों
का अखिल भारतीय परिसंघ

***

सवर्ण अत्याचार - सहारनपुर एक श्रंखला

वैभव मिश्रा

दलितों के साथ सैकड़ों वर्षो से अत्याचार होता आया है और आज भी बदस्तूर जारी है। इसके लिए उच्च जाति के लोग जिम्मेदार है यह हम सभी लोग जानते है। लेकिन इसमें सरकार का भी उतना ही दोष है जितना उच्च जाति वालो का है। अगर सरकार स्वच्छता, शौचालय के लिए बड़े स्तर पर एक जागरूकता मिशन को चला सकती है जिसमे सबके सहयोग के लिए आहवाहन किया जाता है तो ऐसे में दलितों के साथ भेदभाव और अत्याचार को खत्म करने करने के लिए क्यों नही पूरे देश को एकजुट कर इसकी शुरुआत की जाये। क्यों एक दलित का साथ केवल एक दलित ही देने के लिए खड़ा होता है। क्या सरकार उच्च जाति वालों को दलितों के प्रति व्यवहार और आचरण के लिए जागरूकता मिशन नही चला सकती। जब बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था, या जब महिलाओं के लिए कई एक्ट बनाये थे तब तो उन्होंने कोई भेदभाव नही किया कि दलित वर्ग के लोगों के लिए संविधान दूसरा होगा और दूसरी उच्च जाति वालों के लिए दूसरा। आये दिन दलितों के साथ अत्याचार होता रहता है और उन्हें केवल उच्च जाति के ही नही बल्कि दूसरे धर्मो से भी अन्याय सहना पड़ता है। ''वर्तमान समय में स्थिति यह है कि यदि कोई धार्मिक दंगा होता है तो भी दलित मारा जाता है और जब बात अधिकार और सम्मान की होती है तब भी दलितों को ही दबाया जाता है, मुसलमान-दलित को हिन्दू समझ कर काट्टा है और हिन्दू चमार समझ कर'' कुल मिलाकर दलित को ही सबसे ज्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ता है।

सहारनपुर में दलितों के साथ क्या हो रहा है किसी से छिपा नही है। उनके घर जला दिए गए उनके साथ मारपीट की जा रही है जिसमे उन्हें अपनी जान भी गँवानी पड़ रही है और जिस तरह का रवैया अभी तक सरकार का दिखा है, दूर-दूर तक स्थिति को सुधरने के हालात नजर नही आ रहे है। दलितों के लिए कई मसीहा बन कर आये लेकिन अभी तक कोई भी उन्हें वह सम्मान दिलाने में सक्षम नही रहा है । जिनमे मायावती जी, डॉ. उदित राज

जी, रामदास अठावले जैसे कई दिग्गज दलितों के लिए अपनी लडाई लड़ रहे हैं । यह दलितों को समझना होगा कि उन्हें किसके साथ आगे बढ़ना है क्या उनके लिए मायावती सही नेता या फिर डॉ. उदित राज या रामदास अठावले। इन सबका आंकलन करना चाहिए और उसके बाद दलितों को एकजुट होकर इनमे से किसी एक का साथ देना चाहिए । मायावती जी स्वयं को यूपी में रहने वालों का अपना मसीहा समझती है और रामदास अठावले महाराष्ट्र में रहने वाले दलितों को लेकिन डॉ. उदित राज ने कभी भी किसी एक राज्य के दलितों के लिए आवाज नहीं उठायी है उन्हें जब भी दलितों के लिए आवाज उठायी है तो पूरे देश के दलितों के लिए इसका उदहारण हर वर्ष दिल्ली के जतंर-मंतर, रामलीला मैदान में देखने को मिलता है और उनके द्वारा किये गए कार्यो को भी । कोई यूँ ही नही अपनी सरकारी नौकरी समाज सेवा के लिए छोड़ता है वो भी जब पद कमिश्नर जैसा हो। जिसमे ऐसे और सम्मान की कमी ही न हो लेकिन इसके बावजूद डॉ. उदित राज ने अपनी आराम की जिंदगी को छोड़कर दलितों के अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष किया ।

आज लगभग 30 वर्ष पूरे हो गए है जब से लेकर अब तक उन पर कभी कोई एक ऊँगली नहीं उठा सका । दलितों को ऐसे नेताओं की जरुरत है और उन्हें आगे आकर उनका साथ देना चाहिए अगर अब भी दलित अपने सही नेत्रत्वकर्ता को पहचानेंगे नही तो दलितों का भविष्य सुधरने वाला नही है । डॉ. उदित राज वह व्यक्ति है जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा दलित मुद्दे संसद में उठाये है मायावती हो या अन्य कोई भी दलित नेता किसी ने भी डॉ. उदित राज के बराबर संसद में आकर दलितों के लिए आवाज नही उठायी है । इसके अतिरक्त अपने 20 वर्ष पुराने संगठन ''अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ'' के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश में समय-समय पर जाते है और दलितों की समस्याओं को समझते है और उसके बाद फिर संसद, मीडिया, और कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत करते है और सरकार से उनके अधिकारों के लिए लड़ते है और लड़ रहे है । उन्होंने अभी तक जो मुकाम हासिल किया है वह कोई सामान्य बात नही है उन्हें इससे दुगनी सफलता मिल जाती अगर दलितों ने बीच में उनका साथ न छोड़ा होता वो भी मायावती के झूठे आरोपों के चलते और जाति विभाजन का भ्रम फैलाकर । साल दर साल हो गए है स्थिति जस कि तस बनी हुई है ऐसे में दलितों और आदिवासियों को अपने पुराने नेता पर भरोसा करते हुए उनका साथ देने के लिए आगे बढे । नहीं तो सहारनपुर जैसी स्थिति अन्य स्थानों पर भी आगे होगी, पलायन के सिवा दूसरा कोई रास्ता न बचेगा और कोई भी सुनने वाला नही होगा और न ही अवाज उठाने आगे आयेगा ।

***

(पृष्ठ शेष 4 का)

के स्कूल में गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही है। 70-80 हजार रूपये

अपने विचार रखते हुए बताया कि किस प्रकार सतयुग से त्रेता, द्वापरयुग व विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय रही। और महिला का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। तब

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने वाला अगर कोई मसीहा बना तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। क्योंकि उन्होंने ही हिन्दू कोड बिल लाकर महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलवाए। आज महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, रोजगार, अनेकों संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इस संगोष्ठी से महिलाओं में जागृति लाने का प्रयास किया गया है।

कार्यक्रम में अनेक महिला वक्ताओं ने जिसमें 'ईस्ट दिल्ली की महिला टीम अध्यक्षा कुमारी वंदना गौतम जी', श्रीमती गीता जी, सुजाता जी, रानी शंकर जी, सरिता जी व स्पेशल लीगल विषय पर महिलाओं के संवैधानिक अधिकार पर एडवोकेट सुमन तंवर जी ने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए । साथ ही श्री टी. आर मीना जी व फैस्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवीन्द्र जी ने भी महिला जागृति से संबधित विचार रखे व मीनू केलकर आदि ने मंच व्यवस्था पर अपना भरपूर सहयोग दिया।

इसके अलावा जिनका कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा वे हैं श्री हरेन्द्र जी, जोगेंद्र जी, रविंद्र जी, अर्चना, सरिता, कविता ,रीटा सरकार, सुनीता केम, वंदना, सुमन तन्वर, मीनू केलकर, डा रूचिता पाल आदि । इनको पूरी महिला प्रकोष्ठ की टीम धन्यवाद देती है।

– सविता कदियान पंवार
आल इंडिया परिसंघ–
महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय संयोजक
– 9873944026

***

(पृष्ठ शेष 3 का)

कगार पर आ जाएगा, इसलिए दलित समाज को बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को भूलना नहीं चाहिए तथा अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह भी दी।

डॉ. उदित राज ने आए हुए लोगों से कहा कि लेने से पहले कुछ देने की उम्मीद करनी चाहिए बाबासाहब का आरक्षण सबको याद रहता है और फायदा सब उठाते हैं। लेकिन बाबासाहब की 22 प्रतिज्ञा, बाबासाहब का योगदान किसी को याद नहीं रहता। अगर क्षेत्र में बाबासाहब का कोई प्रोग्राम या विचार गोष्ठी की जाती है। तो आरक्षण ले रहे लोगों को प्रोग्राम में आने का समय तक नहीं मिल पाता लेकिन वहां कोई भागवत गीता, कथा, सत्संग होता है तो हमारे समाज का सारा परिवार उस प्रोग्राम में जाता है और वहां अपनी मेहनत की कमाई हजारों रूपये खर्च करते हैं, चाहे उन पर कर्ज हो जाए। लेकिन उस ब्राह्मण को मजबूत करने का काम करते और अपने आप को कमजोर करते हैं। जो लोग बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण लेते है, वही लोग बाबा साहब के मिशन के साथ बेईमानी करते हैं। इनको पता होता है कि किस विभाग में कितना आरक्षण हमको मिल रहा है। या यूं कहें कि बाहर किसी विभाग में नौकरी में जगाह निकली है तो अपने गरीब पड़ोसियों तक को भनक नहीं पड़ने देते। उन कामों को खुद कर लेते हैं, डॉ. उदित राज ने समाज के लोगों से अपील की कि कुछ लेने से पहले कुछ देना सिखो।

विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने दलितों के लिए ही नहीं बल्कि सभी समाज के लिए काम किया था। संविधान या कानून संपूर्ण समाज की विचारधारा को तो नहीं बदल सकता पर सच है कि परिवर्तन की राह बदल सकता है। वीर सुर्या टाइम्स के संपादक एवं परिसंघ के मुस्ताफाबाद के विधानसभा अध्यक्ष मनीष सूर्यवंशी आए हुए हजारों लोगों का धन्यवाद एवं अभिनन्दन किया उन्होंने बताया कि बड़े दुख की बात है कि मुस्ताफाबाद विधानसभा में भारतरत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से कोई भवन नहीं, मार्ग नहीं, कोई चौक नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं उन्होंने माननीय सांसद व माननीय विधायक के सामने अपनी बात रखी माननीय सांसद एवं माननीय विधायक जी ने पूरा अश्वासन नहीं पूर्ण विश्वास दिलाया कि बाबा साहब के नाम से भवन, मार्ग, चौक, लाइब्रेरी शिव बिहार, मुस्ताफाबाद में नहीं दिल्ली की 70 विधानसभाओं में होना चाहिए और मनीष सुर्यवंशी ने बाबासाहब डॉ. अंबेडकर की विचारधारा को घर-घर पहुँचाने की बात की।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कालीचरण जी ने की व मंच का संचालन डॉ. आर. के. गोविल ने किया तथा कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्रालय के निदेशक नेतराम ठगेला, शिल्पकार टाइम्स के संपादक आर. पी. टमटा, शिव विहार निगम पार्षद रीना कटारिया, जोहरीपुर के निगम पार्षद कन्हैयालाल, पूर्व चैयरमैन संजय कौशिक, नरेंद्र सिंह कटारिया, राजेंद्र सूर्यवंशी, राहुल, के. एल. राजौरा, सुरजीत राठी, ओमप्रकाश पिन्डोरा, पुष्पेंद्र, सतीश, धर्म सिंह, रजनी सूर्यवंशी, नरेंद्र राजौरा आदि लोगों ने भाग लिया।

***

Reform, Despite Nay-Sayers

The history of the abolition of sati is instructive for the triple talaq debate

Rajesh Kochhar

The Supreme Court has concluded the arguments on triple talaq. When can a religious practice be considered integral to a religion is a question that has engaged jurists the world over. The Supreme Court is conscious of the complexity of the issue and is treading cautiously. It appears likely that the Court would skirt the issue and be content with an anti-instant divorce advisory from the All India Muslim Personal Law Board.

The majoritarianists, however, have made Muslim personal law a part of their political agenda. An advocate, Ashwini Upadhyay, ominously told the Court that, "tomorrow there would be a Hindu Personal Law Board to take a rigid stand on Hindu practices". The learned advocate should have known that no such board can come into existence because Hindu personal law as an enforceable entity has never existed.

Speaking at public meetings, central minister M. Venkaiah Naidu claimed that the Hindus abolished sati. Similarly, he'd like Muslims to end triple talaq. Naidu's assertion on sati seems to be a matter of convenience; it is not borne out by facts on record. Sati was banned in December 1832, not on the demand of the Hindus, but as a personal initiative of the governor general, William Bentinck. Sustained campaigns against sati came from Christian missionaries rather than Hindus.

Sati was banned in 1832, not on Hindu demand, but as an initiative of the governor general, William Bentinck Campaigns against sati came from Christian missionaries rather than Hindus.

Reforms came not because the Hindus asked for them but because dedicated campaigners convinced the colonialists they enjoyed scriptural support.

The British recognised sati as a barbarian practice, but were aware that it had been in vogue since ancient times and enjoyed scriptural support. Was it to be treated as a criminal act and banned, or was it to be condoned on the stated principle of non-interference in religious matters? The colonial administration took 40 years to make up its mind. As early as 1789, it instructed its officials in the mofussil not to use official power to prevent sati on the grounds that it was "authorised by the tenets of the religion of the Hindoos". In 1813, guided by court pandits, the government decided to regulate the practice, thus unwittingly encouraging it.

In 1817, the universally respected chief pandit at the supreme court, Mrityunjaya Vidyalankar Chattopadhyaya, was officially asked to give a vyavastha (ruling) on sati. After consulting some 30 texts belonging to various schools, he concluded that though burning was termed optional, it was still not to be recommended. Vidyalankar's tract became the unacknowledged starting point for Ram Mohan Roy in his anti-sati campaign. To build his case, Roy had to selectively enlist the support of ancient rishis like Manu and Yajnavalkya, while condemning authorities such as Gotama. Till this time, the anti-sati campaign was exclusively all-European involving missionaries, government and British public opinion. With Roy, sati became a topic of debate among Hindus. Had Bengal's Hindu leadership rallied behind Roy, the colonial administration would have had no difficulty in banning sati immediately. But it was not Hindus versus sati, but conservative Hindus versus Roy and his supporters, backed by Christian missionaries.

Even though Roy advised Bentinck against any direct action, once the enactment was made, he marshalled all resources in its support. The matter finally came to a close in 1832 with the Privy Council upholding the ban. While now, we take pride in the abolition of sati, in its time, the court of directors had to defend their action in front of their King, facing objections from the Hindus.

A generation later, when in 1855, Ishwar Chandra Vidyasagar campaigned against widow remarriage, his opponents far outnumbered supporters. The government did not go by head-count, but by Vidyasagar's assertion that, "this custom is not in accordance with the Shastras, or with true Hindu law".

Hindu social reforms thus came about not because the community at large asked for them, but because a dedicated band of campaigners convinced the colonialists that they enjoyed scriptural support. The moral is clear. Scriptures are not a monolith. Be it a defensive minority or an aggressive majority, the agenda should be modern, and the scriptures interpreted accordingly.

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/triple-talaq-reform-despite-nay-sayers-muslim-personal-law-aimplb-sati-4706218/

***

(Cont page 8)

In this way at each stage except the beginning the form will have to be downloaded. In our country whenever there is talk or discussion for the progress of the nation many negativity are spread like - Inspector Raj, increase paperwork, etc. Negativities are spread.

The irony is that if it was in personal interest, even neighour would have not known its benefits. Since it is tax liability to the government and mechanism to maintain the transaction in benefit the products and services but it will help growth all over. Due to digitization even those not wanting to go digital will have to "walk the talk" - 'toe the line' for the sake of the nation. Why the fear? This is due to those (approx. 30%) who were making manual invoices will now have upgrade themselves and go digital. They need to understand that the more they show sales and growth the more they will benefit. The more taxes are paid the more the business will grow. Businessmen have accumulated black money due to which they are forced to do illegal deeds like - Hawala transaction, donations, etc. etc. Worldwide it is visible that those nations that are using technology and have gone digital have grown faster and bigger. Take South Korea as an example - they have grown 26% faster than India.

The Modi Government has finally introduced GST. The government does not have a private agenda in introducing GST, so why have the people already decided that GST will not be beneficial. Why the fear.....this has already taken place the world over and is successful. It is a tried and tested formula to success and growth. There are two basic fears –

i) all transaction to be transparent – Digitization

ii) we Indians do not accept change easily.

***

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:

Five years : Rs. 600/-

One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 20 ● Issue 16 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 July, 2017

Discrimination of UPSC

Results for the Civil Services Examination, 2017 conducted by UPSC came out on 31st May, 2017. 1090 candidates got selected out of lakhs of aspirants. It is a well known fact that selection is a three stage process. Where first stage is preliminary, second is mains and third stage is interview. For the first and second stages, Board does not have separate provisions for aspirants of different categories, while for the interview stage, separate boards are designed for different categories of candidates. The purpose behind different boards for different groups is to ensure level playing field for candidates belonging to Dalit and backward communities. When the interview marks for different categories candidates was analysed, it was found that provision of separate board for candidates belonging to weaker communities is more harmful than being beneficiary.

163 candidates of Scheduled Castes, 89 candidates from Scheduled tribes, 347 of backward classes and 500 candidates of general category were selected for various services. In the interview, the Scheduled Castes candidate were given an average of 163, 166 was average score for candidate from Scheduled tribe category, 164 for the backward classes candidate and 170 marks for the general category candidate. Such arrangements for interview were made for the purpose that the candidates of different classes should compete among themselves. If it was not so, then there was no necessity to arrange separate interviews. It might have been possible that reserved category candidates would have secured better marks in interview round if interviewers were unaware of their caste. There are such examples also were caste biases are shown by interviewers. Discriminatory practices in our society is committed by members of our society only, not by any Pakistani or Bangladeshis.

There is a large section in societywho believe that less qualified IAS, IPS, IRS, IFS and other services go by getting less marks through reservation and other benefits. They should know that there is no such examination system in the world which will absorb the full potential, virtues and knowledge of any person in a report card. Solving one or two extra questions increases some points and such people pass in the general category, but that does not mean that those who received a little less marks are ineligible. The real test begins when responsibilities are put on officers and quite often the

one who were good with marks, not necessarily lead with their work. As far as the way to develop or talk about personality, they are mostly formed only from home and caste. Those who have got the opportunity to have formal studies for 50 and 100 generations, their children will naturally be better in personality, education and living. Those who have been denied of the benefit for generations, need some extra time and opportunity and eventually they will match up too. Perhaps there is no better example than my experience in Jawaharlal Nehru University. There is some benefit given to the students coming from the rural and backward areas, using which they get admission in the university. In the semester system, such student lag behind during first semester. With time onward, many such students from rural and backward communities starts to catch up with other and by the end many of such students even achieve highest rank in their batch. Overall, the question is, to get the opportunity. Napoleon had said that there is no ability without opportunity. Last year, the first ranker of Union Public Service Commission was from Dalit community. In this year's JEE, the Dalit student has secured first place in the whole country with 100 percent marks, though it is an exception. These exceptions were not possible until the 1960-70 and 80s. Candidates from general categories and good background had an advantage of good education, culture and atmosphere, which was not to candidates from reserved categories. Earlier, difference in cutoffs for different categories were big but slowly the gap is getting reduced and they will end within one or two generation.

Oxford University was established in England in the 11th century. The British came to India with the same educational background and similar standards were followed in the examination of the Civil Services. Britishers only qualified the examiniations, should it be assumed that they were more qualified than the Indian by birth? When Indian were not able to pass the examinations, a movement started under the leadership of Dada Bhai Naroji that Indians should be given opportunities in bureaucracy. When Indian candidates used to get less marks in the examination than the British candidates, and could not pass, then the third class system was introduced, before which only first and second class were present. Now, compared to Europe and the American people, the difference between the Indians and them is very low. There has been a tradition of education for thousands of years in the Jews society, because of which even today it is still ahead of others. That's why the country with a handful of people have the honours of hundreds of Nobel Prizes with them.

The country will be strengthened by participation of all and equality. Those who think that it will affect the quality, their idea is wrong. When the economic condition of the dalits and tribals improves, their purchasing power will increase, then whose stuff will be sold? Obviously, the dalit and tribal are not involved in industries and the market, then benefits will be go the upper castes. Those who show their biases on the lines of caste during interviews, they have only weaken the country. The appeal is that let everyone participate and let the country prosper further.

- Dr Udit Raj,
Member of Parliament
National Chairman,
All India Confederation of
SC/ST Organisations

***

G S T

At the stroke of midnight on 1st July the Goods and Service Tax (GST) was implemented. Even before the implementation there was uncertainty, confusion and negativity. The question arrives that why are we afraid when we have no idea of the difficulty or if there will be any difficulty at all? By and large Society is always opposed to change even where there is no vested interested. For example, when the Telecommunication companies introduced the Mobile Phone they aggressively advertised showing that every farmer or labourer would own a mobile. Many thought it was a joke, questioning how the illiterate/uneducated would be able to use a mobile. Where there is a necessity and self interest even though who do not have competency and yet strive to achieve that. Common people were not familiar with alphabetic and numbers of English, and eventually they learned and started using the mobile. In case of GST, problems are not that much complicated that it can't be implemented. In due course of time online consumption and filing of returns would become friendly.

Due to necessity and interest of the consumer, the mobile was well accepted by all. Very often it was seen that the some uneducated knew more about the technology, apps, ets than many educated. This was because they were curious and interested in the product. In their free time they are able to watch movies, listen to songs, watch the news, etc. Similarly, if given time GST too will prove beneficial – nothing is impossible – Time is of the essence.

It is being rumored that GST will bring many difficulties. It is a known fact that in the beginning all change will bring with its difficulties. The mobile for instance – initially, it was very highly priced, calls would drop while talking, to name a few among a list of other issues, still all owned a mobile. If the taxes were deducted/paid honestly/correctly then there would have been no more problems. Presently, the topic of discussion is that Form 37 needs to be filled in every-time we buy or sell. This is incorrect. In fact, the person who sells will have to fill the form then the same form will be downloaded by the buyer.

(Cont. page No 07)

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya